संसद में आकर जवाब दे सरकार

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 05 अगस्त. संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक खींचतान के बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

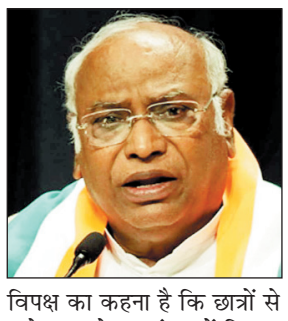

खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार के शीर्ष नेता महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन से दूरी बनाए हुए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से संसद में उपस्थित होकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की मांग की.

खड़गे ने खास तौर पर दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा. विपक्ष का कहना है कि छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और सरकार को पुलिस कार्रवाई से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए. खड़गे ने श्रीराम मंदिर से जुड़े दान और चंदे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने इस संबंध में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. विपक्ष के नेता ने कहा कि संसद में जनता और देश से जुड़े गंभीर विषयों पर चर्चा होना जरूरी है

छात्रों से जबरन माफीनामा लिया गया : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के छात्र अपनी मेहनत, अधिकार और भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में उनका लगातार शोषण किया जा रहा है. राहुल गांधी ने विशेष रूप से परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों मेहनत करते हैं. ऐसे में जब प्रश्नपत्र लीक होने या अन्य कारणों से परीक्षा रद्द होती है तो इसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और उनके सपनों को इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी ने मांग की कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

20 मिनट में 7 धमाकों से धुआं-धुआं दुबई

नई दिल्ली, 05 अगस्त. एक तरफ ओमान और ईरान की वार्ता चल रही है कि खाड़ी में हालात सामान्य हो जाएंगे. होर्मुज पर सेटलमेंट की बात के बीच संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर फिर निशाने पर आ गया. यहां बुधवार को सुबह-सुबह हड़कंप मच गया, जब जाबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार कई जोरदार धमाके हुए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान में धुएं के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

यूएई में ईरान के गुर्गों की करतूत

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक अमीराती अधिकारियों ने दावा किया कि करीब 20 मिनट के भीतर कम से कम 7 धमाके हुए. हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इन विस्फोटों की वजह क्या थी न ही इसका अभी तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है. धमाके जाबेल अली पोर्ट और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हुए, जो यूएई का एक महत्वपूर्ण पोर्ट और फ्यूल डिस्ट्रिब्यूशन का सेंटर माना जाता है. इसके अलावा इसे लॉजिस्टिक्स हब भी कहा जाता है. गनीमत ये है कि अब तक किसी के जख्मी होने या बड़े नुकसान की खबरें नहीं आई हैं.

> घटना के बाद सोशल मीडिया पर धमाकों और आग के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. अमीराती अधिकारियों ने घटना का वीडियो बनाने वाले दो लोगों को हिरासत में लिया है. मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ये धमाके यमन से दागी गई मिसाइलों की वजह से हुए. वहीं अमीरात के स्थानीय मीडिया ने केवल इतना कहा कि कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, लेकिन मिसाइल हमले या किसी अन्य कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की.

मुंबई पुलिस में बड़ा वेतन घोटाला

मुंबई, 05 अगस्त. मुंबई पुलिस विभाग में सामने आए कथित वेतन घोटाले ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ विभाग की आंतरिक निगरानी प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 और 2020 के दौरान 10 ऐसे लोगों के नाम पर करीब 6.50 करोड़ रुपये की तनख्वाह निकाली गई, जो कथित तौर पर मुंबई पुलिस के कर्मचारी थे ही नहीं. इन लोगों ने बिना वर्दी और बिना पुलिस की नौकरी के करीब करोड़ों रुपये का वेतन हासिल किया.

फर्जी नामों से निकले 6.5 करोड़

> मामला करीब छह साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसके सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. जिन 10 लोगों के नाम से वेतन जारी किया गया, उनका मुंबई पुलिस के वास्तविक कर्मचारियों के रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं था. इसके बावजूद वेतन भुगतान की प्रक्रिया चलती रही और कथित तौर पर करीब साढ़े छह करोड़ रुपये की राशि उनके नाम पर जारी हो गई. इस पूरे मामले ने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा किया है कि आखिर बिना नियुक्ति के किसी व्यक्ति का नाम पुलिस विभाग के वेतन रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचा. इतना ही नहीं, यदि इन लोगों को नियमित तौर पर वेतन दिया जा रहा था तो विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की उपस्थिति, नियुक्ति रिकॉर्ड और वेतन भुगतान की जांच के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आई.

फिर कह रहा हूं कि कोई गोली नहीं चली : पात्रा

राहुल के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार

नई दिल्ली, 05 अगस्त। राहुल गांधी की प्रेसवार्ता के कुछ ही समय बाद भाजपा ने उनके आरोपों का जवाब दिया. भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि 20 तारीख को हुए संसद चलो मार्च के दौरान कोई गोली नहीं चली थी.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी भाजपा ने यही बात कही थी और अब भी पूरी जिम्मेदारी के साथ वही दोहरा रही है. पात्रा ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता में छात्र प्रदर्शन में शामिल युवाओं के साथ मंच साझा किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के बाद छात्रों को धमकाया जा रहा है और उनके घरों पर दबाव बनाया जा रहा है. इसके जवाब में संबित पात्रा ने कहा कि उनकी प्रेसवार्ता छात्रों के खिलाफ नहीं, बल्कि राहुल गांधी के बयानों के जवाब में है.

कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को मिला एक साल का विस्तार

नई दिल्ली. सरकार ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन को एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किये. श्री मोहन 23 अगस्त 2024 से गृह सचिव के पद पर हैं. इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और आर्थिक मामले विभाग में संयुक्त सचिव समेत केंद्र और सिक्किम सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. श्री मोहन के पास भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में डिप्लोमा की डिग्री है.

राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

नई दिल्ली, 05 अगस्त. हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, राज्य के विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.

महिपाल ढांडा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की. शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

शिक्षा सुधार, सुशासन और प्रदेश के विकास पर हुई अहम चर्चा

शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का मुद्दा भी सामने आया. स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ने और शिक्षा व्यवस्था में सुशासन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई.

एक नजर में

रांची में छात्रों के आंदोलन का 12वां दिन

रांची. झारखंड में जेएसपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली और प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. लगातार चल रहे प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रशासन और मुख्यमंत्री आवास की ओर से आंदोलन स्थल पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामले में बातचीत की उम्मीद जगी है. रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत और अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश का हवाला देते हुए आंदोलनकारी छात्रों से पांच प्रतिनिधियों का चयन करने को कहा. इन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री आवास ले जाकर सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा गया है. प्रशासन की इस पहल के बाद छात्रों ने तुरंत प्रतिनिधिमंडल के नाम देने से इनकार नहीं किया, लेकिन फैसला लेने के लिए समय मांगा.

अब भारत के बताए रास्ते पर चलेगा नेपाल

काठमांडू. नेपाल की सियासत में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है. काठमांडू के प्रधानमंत्री बालेन शाह, जो कल तक अपने तरीके से सब कुछ बदलने का दावा करते थे, अब उन्हें भी समझ आ गया है कि जमीनी विकास और गवर्नेंस का असली मॉडल तो भारत के पास ही है. बड़े-बड़े दावों और भाषणों से जब ग्राउंड पर काम करना मुश्किल होने लगा तो आखिरकार नेपाल के हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने आई है. यही वजह है कि अब नेपाल ने अपने शहरों और गांवों की सूरत बदलने के लिए सीधे भारत का रुख किया है और अपने 21 खास मेंबर्स को हैदराबाद भेजा है. भारत के विदेश मंत्रालय की एक खास 'कैपिसिटी बिल्डिंग' पहल के तहत नेपाल के कोशी प्रांत से 21 सदस्यों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल स्टडी टूर पर भारत आया है. इस टीम में नेपाल के इलाम, पंचथर, ताप्लेजुंग और तेरहथुम जिलों के मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष और बड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं.

6.64 करोड़ लोगों ने कराया पंजीकरण

नई दिल्ली, 05 अगस्त. सरकार ने आज कहा कि मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर 6.64 करोड़ से अधिक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल ने रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

- नौकरी चाहने राष्ट्रीय कॅरियर सेवा पोर्टल
- लोस में मांडविया ने दी जानकारी

सिंगल विंडो प्लेटफार्म

उन्होंने कहा कि पोर्टल की स्थापना के बाद से अब तक 6.64 करोड़ से अधिक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों ने इस पर पंजीकरण कराया है. 15 जुलाई तक पोर्टल पर 17.68 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां उपलब्ध थीं और 2.89 करोड़ सक्रिय नौकरी चाहने वाले इससे जुड़े हुए थे. मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल एक डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जो नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं को एक मंच पर लाता है. पोर्टल के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रोजगार मेले, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं.

अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश

■ 9 संदिग्ध गिरफ्तार ■ 4 नाबालिग शामिल

अमृतसर, 05 अगस्त. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित होने वाले कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है.

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में कुल नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल, चार पेट्रोल बम और नौ जिंदा कारतूस बरामद करने की जानकारी दी है. गिरफ्तार संदिग्ध कथित तौर पर पाकिस्तान

की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े विदेशी संचालकों के संपर्क में थे. जांच एजेंसियों को आशंका है कि नेटवर्क का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़ना, संवेदनशील स्थानों की निगरानी करना और क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करना था. जांच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने का दावा किया गया है. पुलिस के मुताबिक संदिग्धों ने रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी के लिए कैमरे लगाए थे. इन कैमरों से प्राप्त दृश्य कथित तौर पर विदेश में मौजूद संचालकों के साथ साझा किए गए. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किन स्थानों की निगरानी की गई और यह जानकारी किस उद्देश्य से जुटाई जा रही थी.

आज का इतिहास

1925: सुरेन्द्र नाथ बनर्जी का निधन.
1926: अमेरिकी तैराक गेरट्रुड एडर्ले इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनीं.
1945: जापान के हिरोशिमा में अमेरिकी विमानों ने एटम बम गिराये.
1960: क्यूबा ने देश की तमाम संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया.
1986: भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म.
1990: पाक के राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया.

नए सिरे से दिशा केस की जांच हो

दिशा के पिता बोले- हमारे पास सबूत हैं

मुंबई, 05 अगस्त। दिशा सालियान की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर कानूनी चर्चा के केंद्र में आ गया है. दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. पिता का दावा है कि उनकी बेटी के साथ अनहोनी हुई थी और इस संबंध में उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं.

> सतीश सालियान ने शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं, जिसमें दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था. उनका कहना है कि बेटी के शरीर पर ऐसे चोटों के निशान नहीं थे, जो ऊंचाई से गिरने के कारण होने चाहिए थे. इसी आधार पर उन्होंने मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे दोबारा देखने की मांग की है. मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. अदालत ने मुंबई पुलिस से सवाल किया है कि जब दिशा के पिता ने हत्या का संदेह जताते हुए शिकायत की थी, तो उस शिकायत के आधार पर प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई. अदालत ने पुलिस के रवैये और मामले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी नाराजगी जताई है.

बांग्लादेश बन गया है पाकिस्तान : हसीना

वर्चुअल संबोधन में छलका शेख हसीना का दर्द

ढाका/नई दिल्ली, 05 अगस्त. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगभग दो वर्ष बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया. पूरे कार्यक्रम के दौरान उनका कैमरा बंद रहा, लेकिन उन्होंने देश की मौजूदा

- दो साल से दर्द में है बांग्लादेश : पूर्व पीएम
- देश में हिंसा और डर का माहौल

परिस्थितियों, अपने निर्वासन और परिवार की यादों को लेकर भावुक बातें साझा कीं.

अपने संबोधन में हसीना ने कहा कि वह केवल पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के रूप में भी लोगों से बात कर रही हैं. उन्होंने 15 अगस्त 1975 को अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दर्द आज भी उनके साथ है. उन्होंने अपने छोटे भाई को याद करते हुए कहा कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी और युवा नेता थे, जिनकी स्मृति हमेशा उनके दिल में रहेगी.

हसीना ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में बांग्लादेश ने भय, हिंसा और अस्थिरता का दौर देखा है. उनके अनुसार यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिसके निर्माण के लिए 1971 के मुक्ति संग्राम में लाखों लोगों ने बलिदान दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान 450 से अधिक पुलिस थानों में आग लगाई गई, सरकारी इमारतों पर हमले हुए और कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करने वाले सुरक्षा बलों को बाद में कठघरे में खड़ा कर दिया गया.

> प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने आरोप लगाया कि अगस्त 2024 के बाद हजारों लोगों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस हिरासत में मौतों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं. उनके अनुसार, राजनीतिक हिंसा के मामलों में दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है.

हस्तियों के ट्वीट

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि जब अनुच्छेद 370 को हटाने वाला ऐतिहासिक बिल पास हुआ, तब मैं संसद का सदस्य था. साथ ही, यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे 5 अगस्त को राज्यसभा में और फिर 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा में बोलने का मौका मिला.

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के अटूट संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर ने शांति, सुशासन, विकास और नए अवसरों की दिशा में नई गति प्राप्त की. यह निर्णय 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर है.

जवाब | **जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा : विदेश मंत्रालय**

पाक को भारत के मामलों में बोलने का हक नहीं

नई दिल्ली, 05 अगस्त. भारत ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में मनाये गये तथाकथित यौम-ए-इस्तेहसाल (विरोध दिवस) पर की गई टिप्पणियों को भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आतंरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से

हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की झूठ फैलाने की हताश कोशिशों का मकसद अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र होने की स्थिति से अंतरराष्ट्रीय ध्यान हटाना है.

> प्रवक्ता ने कहा ,भारत, पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ़ दुर्भावनापूर्ण प्रचार फैलाने के लिए तथाकथित यौम-ए-इस्तेहसाल मनाने की राजनीतिक बेतुकी बातों और बेकार कोशिशों को पूरी तरह से खारिज करता है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को किए गए संवैधानिक बदलाव पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला हैं. इन फैसलों से इस क्षेत्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है. पाकिस्तान को उन मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं. श्री जायसवाल ने कहा कि झूठ फैलाने की पाकिस्तान की हताश कोशिशों का मकसद केवल अंतरराष्ट्रीय ध्यान को अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र होने की स्थिति से हटाना है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन को देख रहा है. हाल के सप्ताहों में, स्थानीय लोगों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने घातक हिंसा, लक्षित हत्याओं और कठोर प्रतिबंधों का सहारा लिया है.